

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2228
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

भारत में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना की स्थिति

†2228. श्री राजू बिष्ट

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना की वर्तमान स्थिति, विशेषकर जुलाई 2025 तक अस्पताल में विस्तरों की उपलब्धता की राज्य-वार स्थिति क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन जैसी विभिन्न योजनाओं और संबंधित योजनाओं के अंतर्गत विशेषकर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में स्वास्थ्य देखभाल में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;
- (ग) दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में विशेषकर स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और
- (घ) उक्त जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी), ब्लॉक जन-स्वास्थ्य केन्द्रों (बीपीएचसी) में स्थापित स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस 2022) के अनुसार, प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 विस्तर उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार, 20,000 से 30,000 की जनसंख्या को कवर करने के लिए 6 इनडोर/ऑफर्वेशन बेड वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एएएम-पीएचसी), 80,000-1,20,000 की जनसंख्या को कवर करने के लिए 30 विस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), 1,00,000-5,00,000 की जनसंख्या को कवर करने के लिए 31-100 विस्तर वाले उप-जिला अस्पताल और 30,00,000 तक की जनसंख्या को कवर करने के लिए 101-500 विस्तर वाले जिला अस्पताल स्थापित किए जाने हैं।

हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) 2022-23 (अवसंरचना और मानव संसाधन), जिसे पहले ग्रामीण

स्वास्थ्य सांख्यिकी के रूप में जाना जाता था, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित है में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 31.03.2023 तक भारत में पीएचसी, सीएचसी, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में 8,18,661 बिस्तर उपलब्ध थे।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)वार उपलब्ध बिस्तरों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की यह प्राथमिक ज़िम्मेदारी है कि वे आवश्यकता और निधियों की उपलब्धता के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के प्रयास करें। तथापि, केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के उनके प्रयासों में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता प्रदान करती है। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम):** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करती है।

एनएचएम के तहत भवन अवसंरचना के विकास के लिए वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 और विगत दो वित्त वर्षों यानी वर्ष 2024-25 और 2023-24 के दौरान स्वीकृत निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2025-26	2024-25	2023-24
1	पश्चिम बंगाल	20223.75	8,735.08	10,840.43

वर्ष 2019 से दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों सहित पश्चिम बंगाल राज्य के लिए स्वीकृत स्वास्थ्य परियोजनाओं का विवरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है:

<https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=62&lid=75>

- पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम):** कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटकों के साथ (सीएस) केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसकी योजना अवधि (वर्ष 2021-22 से 2025-26) के लिए 64,180 करोड़ रुपये का परिव्यय है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को वित्त वर्ष 2021-26 के लिए 10609 भवन रहित-एएएम, 5456 शहरी-एएएम, 2151 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू), जिला स्तर पर 744 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और 621

गहन क्रिटिकल केयर ब्लॉकों (सीसीबी) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण हेतु 33,081.82 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

- पीएम-अभियान के सीएसएस घटक के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल राज्य को वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की योजना अवधि के दौरान 385 भवन रहित उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी), 204 शहरी-आयुष्मान आरोग्य मंदिर (यू-एएएम), 23 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला (आईपीएचएल) और 22 गहन चिकित्सा परिचर्या ब्लॉक (सीसीबी) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए 1309.32 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
- दार्जिलिंग जिले में 4.99 करोड़ रुपये की लागत से 9 भवन रहित उप-केंद्र एएएम, 1.25 करोड़ रुपये की लागत से 1 आईपीएचएल और 23.75 करोड़ रुपये की लागत से 1 सीसीबी को मंजूरी दी गई है। जबकि कलिम्पोंग जिले में 1.25 करोड़ रुपये की लागत से 1 आईपीएचएल को मंजूरी दी गई है।
- **15वां वित्त आयोग (एफसी-XV):** पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी -XV) ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। पंद्रहवें वित्त आयोग (XV- एफसी) स्वास्थ्य अनुदान के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल राज्य के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की 5 वर्ष की अवधि के लिए 1551 भवन रहित एसएचसी, 80 भवन रहित पीएचसी, 7 भवन रहित सीएचसी, 341 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाईयों और 1584 शहरी-एएएम की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए 4318.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

भारत में पीएचसी, सीएचसी, एसडीएच, डीएच व मेडिकल कॉलेजों में बिस्तरों की संख्या

क्रम सं.	संघ राज्य क्षेत्र	(31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार)				
		पीएचसी	सीएचसी	उप जिला/ उप मंडलीय अस्पताल	जिला अस्पताल	जिला अस्पताल
1	आंध्र प्रदेश	8712	6400	5400	2600	12583
2	अरुणाचल प्रदेश	397	594	लागू नहीं	1151	350
3	असम	3166	6218	844	3677	9343
4	बिहार	5596	8039	2459	4575	7251
5	छत्तीसगढ़	5015	6726	629	3542	4458
6	गोवा	183	210	253	600	1342
7	गुजरात	9422	11167	4492	3257	17899
8	हरियाणा	2183	3079	1581	3647	3660
9	हिमाचल प्रदेश	1005	969	3665	1924	2632
10	झारखण्ड	1229	3647	534	3215	2900
11	कर्नाटक	15112	6500	14530	6174	13712
12	केरल	5727	6371	8347	15113	7175
13	मध्य प्रदेश	8640	10590	9721	16650	5850
14	महाराष्ट्र	18276	15004	7903	4108	16998
15	मणिपुर	420	365	10	551	1449
16	मेघालय	1127	867	40	1960	594
17	मिजोरम	655	240	70	903	500
18	नगालैंड	706	325	लागू नहीं	1017	लागू नहीं
19	ओडिशा	1501	6290	1946	7288	9291
20	पंजाब	1688	3711	2509	3931	3160
21	राजस्थान	13866	23820	2500	9474	17131
22	सिक्किम	257	28	लागू नहीं	400	लागू नहीं
23	तमिलनाडु	10025	12582	21978	7695	29888
24	तेलंगाना	4662	3320	5400	2270	5960
25	त्रिपुरा	918	630	900	1260	727
26	उत्तराखण्ड	2111	1699	2035	1511	1850
27	उत्तर प्रदेश	13548	26157	लागू नहीं	22812	14726
28	पश्चिम बंगाल	7640	11205	13110	7599	25086
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	230	210	लागू नहीं	220	700
30	चंडीगढ़	23	120	100	527	3096
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	177	132	100	240	589
32	दिल्ली	12	लागू नहीं	431	9789	12060
33	जम्मू और कश्मीर	3955	2769	लागू नहीं	1862	5420
34	लद्दाख	320	190	लागू नहीं	370	लागू नहीं
35	लक्षद्वीप	40	90	70	50	लागू नहीं
36	पुदुचेरी	185	120	लागू नहीं	1853	2794
	अखिल भारतीय/कुल	148729	180384	111557	153815	224176
